THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) The Government has taken a view that the work relating to the protection of the ridge would be exclusively vested in *the* DDA which is also butressed by vesting the powers under the Indian Forests Act, 1927 and Forests (Conservation) Act, 1980 in the DDA.

Contribution for partipating States in NCR Plan

1196. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of participating States which have contributed their share to the National Capital Region Finance Corporation; and

(b) by when the plan is likely to take! off?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) The Government has not taken any decision regarding the setting up of a National Capital Region Development Finance Corporation and, therefore, the question of contribution by participating States in the proposed Corporation does not arise.

(b) The NCR Planning Board has an approved outlay of Rs. 200 in the VIII Year Plan, in the State Sector which is an increase from Rs. 35 crore in the VII Plan. Thus a considerable step-up of investment is envisaged in the current Plan period, in order to achieve the objectives of the NCR Plan.

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना–II

@1197. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई महानगर में उपनगरीय रेलगाड़ियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए "मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना II" नामक योजना सरकार के पास भेजी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) इस परियोजना के संबंध में निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने विश्व बैंक की वित्तीय मदद पाने हेतु बम्बई नगर परिवहन परियोजना–II (बूट पी–II) प्रस्तुत की है। परियोजना में मौजूदा सड़कों में सुधार विस्तार के साथ-साथ अतिरिक्त फ्लाई ओवरों, सड़कों के निर्माण, मौजूदा उपनगरीय रेल सेवाओं में बढ़ोतरी और अतिरिक्त उपनगरीय रेलवे लाइनों का प्रावधान शामिल है। परियोजना की लागत लगभग 2248.88 करोड़ रुपये है, जिसमें उपनगरीय रेलवे में बढ़ोतरी के लिये 1304.88 करोड़ की राशि शामिल है। तथापि, विश्व बैंक ने कहा है कि वे परियोजना के लिये तभी वित्त प्रदान कर सकते हैं जब उसके उपनगरीय रेलवे घटक का वित्त पोषण देशी संसाधनों द्वारा किया जाए। तदनुसार राज्य सरकार से बूट प्रोजक्ट–II की रेलवे परियोजना के वित्त पोषण के लिये एक उपयुक्त वित्त पोषण पैकेज का सुझाव देने के लिये कहा है।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 798, 8–12–1993 से स्थानांतरित।